बोर्ड परीक्षाओं में छलांग मारते प्राप्तांको के मायने क्या हैं?

माध्यमिक स्कूलों में पढ़ाई–लिखाई को आनन्दपूर्ण, रचनात्मक, विश्लेषणात्मक और सहभागी बनाने की जरूरत है जिससे कि बच्चों में सोचने की क्षमता विकसित की जा सके।

– हरिवंश चतुर्वेदी
डायरेक्टर, बिमटेक

पिछले दिनों सीबीएसई और आईसीएसई बोर्ड़ों के 10वीं और 12वीं के परीक्षाफल घोषित हो गये। इन दिनों परीक्षा फलों की घोषणाओं का सीजन है। अगले कुछ दिनों में राज्य स्तरीय माध्यमिक बोर्डों के नतीजे भी लगातार आने हैं। इस के बाद अगले महिने से ही कालेजों और यूनिवर्सिटियों में दाखिलों का सीजन शुरू हो जायेगा। यह सही वक्त होगा जब कि हमारे देश की स्कूली शिक्षा की भावी दिशा पर राष्ट्रीय विमर्श होना चाहिये।

सीबीएसई ने विगत 2 मई को 12वीं कक्षा के जो नतीजे घोषित किये हैं, उनमे 83.4 प्रतिशत परीक्षार्थी उत्तीर्ण हुए हैं। इन में से 95000 विद्यार्थियों ने 90 प्रतिशत या उससे अधिक और 17693 विद्यार्थियों ने 95 प्रतिशत या उससे अधिक अंक हासिल किये हैं। इस परीक्षा में दो लड़कियों, हंसिका शुक्ला और करिश्मा अरोड़ा ने कुल 500 में से 499 अंक प्राप्त कर समूचे देश में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। देश के कुछ खास इलाकों के बच्चों का 12वीं का परीक्षाफल राष्ट्रीय औसत (83.4 प्रतिशत) से ऊंचा रहा है। इन में त्रिवेन्द्रम क्षेत्र का नतीजा 98.2 प्रतिशत चेन्नई क्षेत्र का 92.9 प्रतिशत और दिल्ली का 91.9 प्रतिशत रहा है।

सीबीएसई के 12वीं कक्षा के नतीजों की तरह 10वीं कक्षा के घोषित नतीजों में भी परीक्षार्थियों पर लगता है अंको की वर्षा हुई है। इस साल 91.1 प्रतिशत परीक्षार्थी पास हुए जबकि पिछली साल यह प्रतिशत 86.7 ही था। इस परीक्षा में 13 विद्यार्थियों ने कुल 500 प्राप्तांको में से 499 प्राप्तांक हासिल किये हैं। 25 विद्यार्थियों को 498 और 59 विद्यार्थियों को 497 प्राप्तांक मिले हैं। सीबीएसई की 10वीं की परीक्षा में 57,256 विद्यार्थियों ने 95 प्रतिशत से ऊपर और 2.25 लाख विद्यार्थियों ने 90 प्रतिशत से ज्यादा अंक हासिल किये है।

इस वर्ष सीबीएसई की वार्षिक परीक्षाओं में 31 लाख विद्यार्थी बैठे थे जिनमें 13 लाख 12वीं की परीक्षा में और 18 लाख 10वीं की परीक्षा में बैठे। सीबीएसई के परीक्षाफलों से सभी लोग उत्साहित हैं क्योंकि यह एक संकेत है कि हमारे देश के नौनिहाल पढ़ाई–लिखाई में आसमान को चूमते हुए दिख रहे हैं। निश्चित रूप से इसका श्रेय बच्चों, उनके मां–बाप और शिक्षकों को दिया जाना चाहिये। यहां यह उल्लेखनीय है कि देश के 52 मान्यताप्राप्त स्कूल शिक्षा बोर्डो में सीबीएसई सबसे ज्यादा सुसंगठित, भविष्योन्मुखी और प्रगतिशील बोर्ड है जिसकी स्थापना 1962 में हुई थी।

सीबीएसई और अन्य स्कूली शिक्षा बोर्डों की वार्षिक परीक्षाओं में अंको की वर्षा पिछले कुछ दशकों में लगातार बढ़ती रही है। कुछ दशक पूर्व 85 से 90 प्रतिशत प्राप्तांकों को हासिल कर बच्चे टॉपर बन जाते थे, जो कि आज असंभव होगा। अंको की बढ़ोतरी के कई कारण

हैं जिनमे एक प्रमुख कारण है भारतीय मध्यवर्ग में शिक्षा के माध्यम से संपन्नता और खुशहाली हासिल करने के प्रति बढ़ता हुआ आत्मविश्वास। 1991 से पूर्व आर्थिक रूप से संपन्न होना उद्योगपतियों, व्यवसायियों, राजनेताओं और कुलक वर्ग के लिये हो मुमकिन था। उदारीकरण के दौर में भारतीय और विदेशी कंपनियों में मध्यवर्गीय युवाओं के एक बड़े वर्ग को मोटी तनख्वाह पर नौकरियां मिलने का जो सिलसिला शुरू हुआ, उसकी रफ्तार 2008 में जाकर ही धीमी हुई। ध्यान रहे कि 2008 में विश्वव्यापी मंदी का असर भारतीय अर्थव्यवस्था पर भी पड़ना शुरू हो गया था।

पिछले 60 वर्षों में आईआईएम, आईआईटी, और एनआईटी से निकल लाखों प्रतिभाशाली युवा देश से पलायन कर के यूएसए, कनाड़ा, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया में जाकर बस गये। अमरीका की सिलीकन वैली में बसे हुए अनेक भारतीय अब अरबपति और खरबपति की श्रेणी में आ चुके हैं। इन के कैरियर ग्राफ को देखा जाये तो यह पाया जायेगा कि वे सभी किसी नामचीन संस्थान से ग्रेजुएट हैं और उन संस्थानों में दाखिला का मुख्य आधार 12वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षा में उनकी ऊंची मेरिट रही होगी। यह भी संभव है कि विदेश जाकर बसे हुए आईटी उद्यमियों अथवा प्रोफेशनलों में ज्यादातर केन्द्रीय विद्यालयों के विद्यार्थी रहे होंगे या 12वीं में सीबीएसई बोर्ड के परीक्षार्थी रहे होंगे। **दरअसल सीबीएसई बोर्ड और केन्द्रीय विद्यालय, दोनो संस्थाएं भारत की स्कूली शिक्षा के ऐसे चमकते सितारे हैं, जिन्हे भारतीय मध्यवर्ग ने जीवन में अपने सुनहरे सपनों को साकार बनाने का एक सबल व सुगम माध्यम बना लिया।**

बोर्ड परीक्षाओं में प्राप्तांकों की वर्षा का एक और प्रमुख कारण स्कूली शिक्षकों, ट्यूटरों, अभिभावकों और स्वयं बच्चों द्वारा कठिन अभ्यास के द्वारा उस फॉर्मूले को विकसित करना भी है, जिसे इस्तेमाल करके अच्छे नंबर हासिल किये जा सकते हैं। सीबीएसई की 10वीं और 12वीं परीक्षओं का एक खास पैटर्न होता है जिसे पहचानने के लिये शिक्षकों, ट्यूटरों एवं स्कूलों की खोजबीन चलती रहती है। 11वीं में प्रवेश पाते ही बच्चों को इस ढंग से पढ़ाया जाता है कि ऊंचे स्कोर ला सकें। उन्हें खासतौर से परीक्षा प्रश्नों के उत्तर देने का एक खास तरीका भी सिखाया जाता है जिस में बच्चों को हर विषय में महत्वपूर्ण बातों को समझना और फिर निंरतर अभ्यास करके उसे अपनी याद्दाशत का हिस्सा बनाना होता है। अच्छे अंक हासिल करने के इन नुस्खों को अब बच्चों के मां–बाप भी सीखने लगे हैं क्योंकि घर पर उन्हें यह देखना होता कि उनका बेटा या बेटी उन नुस्खों पर लगातार अभ्यास कर रहे हैं या नहीं। इन में यह भी जरूरी होता है कि बच्चों का ध्यान टी.वी., इन्टरनेट और सोशल मीडिया की तरफ भटके नहीं।

यूं तो देश के सभी माध्यमिक शिक्षाबोर्डों में हर साल प्रतिभाशाली विद्यार्थियों के प्राप्तांक लगातार बढ़ते देखे गये हैं, किन्तु सीबीएसई एवं आईसीएसई बोर्डों में यह प्रवृति काफी प्रबल दिखाई देती है। इन दोनों बोर्डों के अलावा अन्य राज्यस्तरीय बोर्डों में असफल विद्यार्थियों का प्रतिशत भी अधिक होता है। मिसाल के लिये अभी हाल में घोषित तेलंगाना राज्य बोर्ड की 12वीं की परीक्षा में एक तिहाई विद्यार्थी फेल पाये गये और करीब 25 अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों ने इससे दुखी होकर आत्म हत्या भी कर ली। केन्द्रीय और राज्य बोर्डों के नतीजों में भारी

फर्क का कारण परीक्षा देने वाले विद्यार्थी समुदाय की आर्थिक–सामाजिक एवं शैक्षणिक पृष्ठभूमि में भारी अंतर होना है।

बोर्ड परीक्षाओं में लाखों बच्चों के 90 प्रतिशत से ऊपर प्राप्तांक आने से हमारी स्कूली शिक्षा की जमीनी सच्चाईयां नहीं छुप सकती। सीबीएसई की परीक्षाओं मे 500 में से 499 अंक पाने वाले बच्चों के चमचमाते चेहरे टीवी स्क्रीन और समाचार पत्रों के मुखपृष्ठों पर भले ही दिखाई दें, किन्तु यह मानना मुश्किल होगा कि परीक्षा के सभी विषयों में उनकी सिद्धहस्तता का स्तर 'परफैक्शन' के बराबर है।

स्कूली शिक्षा और वार्षिक परीक्षाओं में सुधार की चर्चा काफी समय से चलती रही है। स्कूली पाठ्यक्रम पर देश की शीर्षस्थ संस्था एनसीईआरटी समय–समय पर पाठ्यक्रम फ्रेमवर्क बना कर पठन–पाठन में लगातार सुधार का मार्ग दिखाती रही है। वर्ष 1975, 1988, 2000 और 2005 में पाठ्यक्रम फ्रेमवर्क बदले गये किन्तु केन्द्र एवं राज्य स्तरीय बोर्डों द्वारा उनके प्रभावी परिपालन की समीक्षा करने की जरूरत है। राष्ट्रीय–आंदोलन के दौरान जब–जब स्कूली शिक्षा में सुधार की बातें हुई, महात्मा गांधी, रवीन्द्रनाथ टैगोर, महर्षि अरविन्द, मौलाना अबुल कलाम आजाद जैसे दिग्गजों ने सदैव इस बात पर जोर दिया कि स्कूली शिक्षा सिर्फ रट्टू तोते न बनाये। उनका कहना था कि **स्कूल स्तर पर पढ़ाई लिखाई को आनन्दपूर्ण, रचनात्मक, विश्लेषणात्मक और सहभागी बनाने की जरूरत है जिससे कि बच्चों में सोचने की क्षमता विकसित की जा सके।** सवाल उठना चाहिये कि बोर्ड परीक्षाओं मे क्या बच्चों के भविष्य के लिये जरूरी इन क्षमताओं का कोई मूल्यांकन हो पाता है या नहीं।

इस साल और अगले कुछ वर्षों में 12वीं पास करने वाले बच्चे अगले 3 से 5 वर्षों में अपनी पढ़ाई पूरी कर परिपक्व युवा के रूप में रोजगार के बाजार में प्रवेश करेंगे। यह ठीक है कि इनमें से बहुत अच्छे स्कोर प्राप्त करने वाले युवाओं के हाथों में एक नामचीन कालेज या यूनिवर्सिटी की डिग्री होगी जो उन्हें मोटी सैलरी पर कोई अच्छी नौकरी जरूर हासिल करा पायेगी। किन्तु क्या ये युवा अपने निजी जीवन और कैरियर में उन चुनौतियों का सामना कर पायेंगे जो कि चौथी औद्योगिक क्रान्ति पैदा कर चुकी है?

वर्ल्ड इकॉनोमिक फोरम का कहना है कि सारी दुनिया में आज जितनी नौकरियाँ उपलब्ध हैं उनका 57 प्रतिशत 2030 तक खत्म होने की संभावना है और 2030 में जो कुल नौकरियां उपलब्ध होंगी उनका 20 प्रतिशत अभी भी मौजूद नहीं है। इसका नतीजा है कि अगले 20–25 वर्षों में नौकरियों के लिये जरूरी 'कौशल सूची' हर 3 से 5 वर्ष में बदलती रहेगी। हम एक बड़े विश्वव्यापी बदलाव की ओर बढ़ रहे हैं। भारत इससे अछूता नहीं रहेगा। किन्तु क्या हमारी स्कूली शिक्षा इस बड़े बदलाव का मुकाबला करने की विद्या और हुनर हमारे बच्चों को दे पायेगी?